Inspira-Journal of Commerce, Economics & Computer Science (JCECS)
(A National bi-lingual Quarterly Double Blind Open Access Peer Reviewed Refereed Journal)
ISSN : 2395-7069(Print), Impact Factor: (Cosmos 7.650 & I2OR 5.120), Volume 12, No. 04, October-December, 2026, pp. 109-117

गया में बहुआयामी गरीबी और असमानताः साक्ष्य एवं नीतिगत चुनौतियों की समीक्षा

मुखदेव कुमार यादव[1*] एवं डॉ. कौशल कुमार[2]

[1]शोधार्थी, अर्थशास्त्र विभाग, मगध विश्वविद्यालय, बोधगया, बिहार।
[2]सहायक प्राध्यापक, आर.एल.एस.वाई. कॉलेज, औरंगाबाद, बिहार।

*Corresponding Author: mukhdeoky@gmail.com

Citation: *यादव, मुखदेव एवं कुमार, कौशल (2026). गया में बहुआयामी गरीबी और असमानताः साक्ष्य एवं नीतिगत चुनौतियों की समीक्षा. Journal of Commerce, Economics & Computer Science, 12(04), 109–117.*

सार

बहुआयामी गरीबी में बिहार देश में सबसे ऊपर है, और गया जैसे सामाजिक रूप से विविध जिले में इस चुनौती को समझने के लिए आय के साथ स्वास्थ्य, शिक्षा और जीवन–स्तर के अभावों को भी देखना ज़रूरी है। यह शोध–पत्र उपलब्ध द्वितीयक आँकड़ों के आधार पर गया की स्थिति को बिहार और कुछ तुलनात्मक जिलों के संदर्भ में रखता है और गरीबी घटाने की राह में आने वाली नीतिगत चुनौतियों की समीक्षा करता है। आँकड़े नीति आयोग के राष्ट्रीय बहुआयामी गरीबी सूचकांक (NFHS–4 और NFHS–5 पर आधारित), NFHS–5 के फैक्ट शीट, जनगणना 2011 और बिहार जाति आधारित सर्वेक्षण (2023) से लिए गए हैं। नीति आयोग के अनुसार बिहार में बहुआयामी गरीबों का अनुपात 2015–16 के 51.89% से घटकर 2019–21 में 33.76% रहा, फिर भी यह राष्ट्रीय औसत (14.96%) के दोगुने से अधिक है। अध्ययन के मुख्य निष्कर्ष तीन हैं। पहला, बिहार के भीतर जिलों के बीच गरीबी में बड़ा अंतर है, और गया में 2019–21 में 35.43% लोग बहुआयामी रूप से गरीब थे, जो राज्य औसत (33.76%) के आसपास पर राष्ट्रीय औसत से बहुत ऊपर है। दूसरा, गरीबी सामाजिक समूहों में असमान रूप से बँटी है, और गया में अनुसूचित जाति की आबादी राज्य के सभी जिलों में सबसे अधिक (30.38%) है। इससे अनुमान बनता है कि गया की गरीबी इन समूहों में अधिक होगी, पर यह जिले के जाति–वार आँकड़ों से परखा नहीं गया है। तीसरा, स्वच्छ रसोई ईंधन, उन्नत स्वच्छता, महिला साक्षरता और बच्चों–महिलाओं के पोषण जैसे संकेतकों पर बिहार अब भी राष्ट्रीय स्तर से पीछे है। पत्र के अंत में चुनौतियों को समूहों में बाँटकर लक्षित नीतिगत सुझाव दिए गए हैं।

शब्दकोशः *बहुआयामी गरीबी, असमानता, गया, बिहार, राष्ट्रीय MPI, नीतिगत चुनौतियाँ।*

प्रस्तावना

गरीबी केवल कम आमदनी की समस्या नहीं है। एक परिवार की आमदनी ठीक–ठाक दिखे, फिर भी बच्चे कुपोषित हो सकते हैं, घर में शौचालय या स्वच्छ ईंधन न हो सकता है, और परिवार में कोई भी छह साल की पढ़ाई पूरी न कर पाया हो। इसी कारण दुनिया भर में गरीबी को कई आयामों में मापने की पद्धति अपनाई जा रही है। भारत में नीति आयोग ने संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम (*UNDP*) और

Copyright © 2026 by Author's and Licensed by Inspira. This is an open access article distributed under the Creative Commons Attribution License which permits unrestricted use, distribution, and reproduction in any medium, provided the original work properly cited.

ऑक्सफोर्ड गरीबी एवं मानव विकास पहल (*OPHI*) के साथ मिलकर राष्ट्रीय बहुआयामी गरीबी सूचकांक (*MPI*) तैयार किया है, जो स्वास्थ्य, शिक्षा और जीवन–स्तर के 12 संकेतकों पर परिवारों के अभावों को गिनता है (यूएनडीपी इंडिया, 2023)।

इस सूचकांक में बिहार की स्थिति सबसे चिंताजनक रही है। 2021 की पहली आधार रिपोर्ट में बिहार की 51.91% आबादी बहुआयामी रूप से गरीब पाई गई, जो सभी राज्यों और केंद्रशासित प्रदेशों में सर्वाधिक थी (नीति आयोग, 2021)। 2023 की समीक्षा रिपोर्ट में यह अनुपात घटकर 33.76% हुआ, पर बिहार फिर भी सबसे ऊपर रहा (यूएनडीपी इंडिया, 2023)।

गया बिहार के मगध प्रमंडल का मुख्यालय और राज्य के बड़े जिलों में से एक है। जनगणना 2011 के अनुसार इसकी आबादी 43,91,418 थी, साक्षरता दर 63.67% और लिंगानुपात 937 (प्रति हजार पुरुष पर महिलाएँ) था (जनगणना 2011 पोर्टल)। स्वास्थ्य डोज़ियर 2021 के अनुसार अनुसूचित जाति की आबादी का हिस्सा गया में 30.38% है, जो बिहार के सभी जिलों में सबसे अधिक है (एनएचएसआरसी, 2021)। जहाँ सामाजिक रूप से वंचित समूहों की हिस्सेदारी इतनी बड़ी हो, वहाँ गरीबी और असमानता को साथ–साथ देखना स्वाभाविक है, क्योंकि राज्य–स्तर का औसत जिले की भीतरी विषमताओं को छिपा लेता है।

अध्ययन के उद्देश्य

- उपलब्ध आँकड़ों के आधार पर गया और बिहार में बहुआयामी गरीबी की स्थिति का वर्णन करना।
- बिहार के अन्य जिलों और राज्य औसत से तुलना कर असमानता के स्वरूप को समझना।
- गरीबी घटाने में आने वाली नीतिगत चुनौतियों की पहचान कर सुझाव देना।

शोध–प्रश्नः गया में गरीबी किन पहलुओं (स्वास्थ्य, शिक्षा, जीवन–स्तर) में सबसे गहरी है, और नीतियों के सामने कौन–सी चुनौतियाँ हैं?

पत्र की रूपरेखा इस प्रकार हैः खंड 2 में साहित्य–समीक्षा, खंड 3 में आँकड़े और विधि, खंड 4 में विश्लेषण, खंड 5 में नीतिगत चुनौतियाँ, खंड 6 में सीमाएँ और खंड 7 में निष्कर्ष व सुझाव।

साहित्य–समीक्षा एवं सैद्धांतिक आधार

- **गरीबी मापन की अवधारणा**

अमर्त्य सेन (1976) ने बताया कि गरीबी मापन में दो अलग समस्याएँ आती हैंः पहली, गरीब की पहचान कैसे हो (जैसे गरीबी रेखा तय करना), और दूसरी, गरीबों की जानकारी को एक संख्या में कैसे समेटा जाए। उन्होंने ऐसा नया माप सुझाया जो उस समय प्रचलित मापों की कमियों से बचे। आगे चलकर बहुआयामी दृष्टि विकसित हुई, जिसमें अल्काइर और फ़ोस्टर (2011) की विधि सबसे प्रचलित है। इसमें दो कटऑफ़ लगते हैंः पहला, हर आयाम में यह तय करने के लिए कि व्यक्ति वंचित है या नहीं; दूसरा, कितने आयामों में अभाव होने पर व्यक्ति को गरीब माना जाए। इस विधि का समायोजित हेडकाउंट अनुपात क्रमसूचक (*ordinal*) आँकड़ों के लिए उपयुक्त है और इसे समूहों व क्षेत्रों में बाँटकर देखा जा सकता है, इसलिए जिला–स्तर के विश्लेषण में यह उपयोगी है (अल्काइर एवं फ़ोस्टर, 2011)।

- **भारत का राष्ट्रीय *MPIA***

नीति आयोग की पहली आधार रिपोर्ट *NFHS*–4 (2015–16) पर आधारित थी और इसमें 12 संकेतक तीन आयामों में रखे गएः पोषण, बाल एवं किशोर मृत्यु, प्रसवपूर्व देखभाल, स्कूली वर्ष, स्कूल उपस्थिति, खाना पकाने का ईंधन, स्वच्छता, पेयजल, बिजली, आवास, संपत्ति और बैंक खाता (नीति

आयोग, 2021)। उस रिपोर्ट में बिहार (51.91%) के बाद झारखंड (42.16%), उत्तर प्रदेश (37.79%), मध्य प्रदेश (36.65%) और मेघालय (32.67%) थे, जबकि केरल में यह केवल 0.71% था (नीति आयोग, 2021)।

NFHS–5 (2019–21) पर आधारित 2023 की समीक्षा रिपोर्ट में देश में बहुआयामी गरीबों का अनुपात 24.85% से घटकर 14.96% रहा। ग्रामीण क्षेत्रों में यह 32.59% से 19.28% और शहरी क्षेत्रों में 8. 65% से 5.27% हुआ। बिहार में डच् मान 0.265 से 0.160 तथा गरीबों का अनुपात 51.89% से 33.76% हुआ, यानी 18.13 प्रतिशत अंकों की गिरावट, जो किसी भी राज्य में सबसे बड़ी थी (यूएनडीपी इंडिया, 2023)। ध्यान दें कि दोनों रिपोर्टों में बिहार का आधार–वर्ष आँकड़ा थोड़ा भिन्न है (51.91% और 51. 89%); इस पत्र में तुलना के लिए 2023 की रिपोर्ट के आँकड़े प्रयुक्त हैं।

- **बिहार जाति आधारित सर्वेक्षण।**

2023 में विधानसभा में रखी गई रिपोर्ट के अनुसार राज्य में लगभग 2.97 करोड़ परिवारों में से 94 लाख से अधिक (34.13%) गरीब थे; यहाँ गरीब का अर्थ ₹6,000 या उससे कम मासिक आय वाला परिवार है (द वीक, 2023)। गरीबी का अनुपात अनुसूचित जाति के परिवारों में 42.93%, अनुसूचित जनजाति में 42.70%, पिछड़ा वर्ग में 33.16%, अत्यंत पिछड़ा वर्ग में 33.58% और सामान्य वर्ग में 25.09% बताया गया। मुसहर परिवारों में यह लगभग 54% रहा (जनता वीकली, 2023)। यह सर्वेक्षण आय आधारित है, जबकि MPI अभावों पर आधारित; दोनों के निष्कर्ष एक–दूसरे के पूरक हैं।

- **अनुसंधान–अंतराल।**

उपलब्ध रिपोर्टें मुख्यतः राज्य–स्तर पर निष्कर्ष बताती हैं। जिला–स्तरीय आँकड़े मौजूद हैं, पर उन्हें जाति–संरचना और नीतिगत प्रश्नों के साथ जोड़कर किसी एक जिले के लिए पढ़ने का काम कम दिखता है। यह पत्र इसी दिशा में गया को केंद्र में रखकर एक संकलित समीक्षा देने का प्रयास है।

आँकड़े एवं विधि

यह अध्ययन वर्णनात्मक है और पूरी तरह द्वितीयक आँकड़ों पर टिका है; कोई नया क्षेत्रीय सर्वेक्षण नहीं किया गया। प्रयुक्त स्रोत ये हैंः

नीति आयोग, राष्ट्रीय बहुआयामी गरीबी सूचकांकः आधार रिपोर्ट 2021 (NFHS–4) और समीक्षा रिपोर्ट 2023 (NFHS–5)।

आईआईपीएस, NFHS–5 राज्य और जिला फैक्ट शीट, बिहार (इस पत्र में गया, अररिया, औरंगाबाद, अरवल और बाँका के जिला फैक्ट शीट तथा बिहार राज्य फैक्ट शीट के आँकड़े प्रयुक्त हैं; जिला–आँकड़े वर्धन के CSV संस्करण से लिए गए)।

जनगणना 2011 और स्वास्थ्य डोज़ियर 2021 (बिहार)।

बिहार जाति आधारित सर्वेक्षण 2023 की रिपोर्ट के मीडिया–प्रकाशित आँकड़े।

तुलनात्मक जिलों का चयन। गया की तुलना चार जिलों से की गई हैः औरंगाबाद और अरवल (गया की तरह मगध प्रमंडल के जिले), बाँका (दक्षिण बिहार का जिला) अररिया (नीति आयोग 2023 के अनुसार 2019–21 में राज्य का सबसे अधिक गरीबी वाला जिला, H = 52.07%) और पटना (कम गरीबी वाले छोर का उदाहरण, H = 23.09%)। इस चयन से यह देखा जा सकता है कि गया अपने निकटतम पड़ोस और सबसे अधिक गरीबी वाले जिले, दोनों के मुकाबले कहाँ खड़ा है।

MPI की गणना सरल भाषा में। राष्ट्रीय MPI में स्वास्थ्य, शिक्षा और जीवन–स्तर, तीनों आयामों का भार बराबर (एक–तिहाई) है। हर परिवार को 12 संकेतकों पर %वंचित" या %वंचित नहीं" गिना जाता

है, और उसका भारित अभाव–अंक बनता है। यदि यह अंक 33.33% या उससे अधिक हो तो परिवार बहुआयामी रूप से गरीब माना जाता है (यूएनडीपी इंडिया, 2023)। इसके बाद दो संख्याएँ निकलती हैं:

हेडकाउंट अनुपात (H): कितने लोग गरीब हैं, यानी गरीबों की संख्या को कुल आबादी से भाग देने पर मिला प्रतिशत।

गरीबी की तीव्रता (A): गरीब लोग औसतन कितने अभावों से जूझ रहे हैं, यानी %गरीब कितने गरीब हैं"।

सूचकांक का मान इन दोनों का गुणनफल है: MPI = H ।। उदाहरण के लिए, बिहार में 2019–21 में H = 33.76% और A = 47.40% है, इसलिए MPI = 0.3376 0.4740 = 0.160। मतलब, बिहार का औसत गरीब व्यक्ति लगभग आधे भारित अभावों से जूझ रहा है।

जिला–आँकड़ों की सावधानी। NFHS एक नमूना सर्वेक्षण है, यानी पूरी आबादी की गिनती नहीं, बल्कि कुछ परिवारों से पूछकर निकाला गया अनुमान। जिन जिला फैक्ट शीट का उपयोग हुआ, उनमें हर जिले में लगभग 947 से 979 परिवारों का सर्वेक्षण हुआ (आईआईपीएस, 2020)। इसलिए दो जिलों के बीच एक–दो प्रतिशत अंक का अंतर वास्तविक अंतर नहीं, केवल नमूने का उतार–चढ़ाव भी हो सकता है। इस पत्र में निष्कर्ष तभी निकाले गए हैं जब अंतर बड़ा है। साथ ही, छथ्थ्ै में यह भी दर्ज है कि उस समय आयुष्मान भारत (PM–JAY) पूरी तरह लागू नहीं हुआ था, इसलिए स्वास्थ्य बीमा का आँकड़ा वास्तविक कवरेज से कम हो सकता है (आईआईपीएस, 2020)।

विश्लेषण: बिहार, गया और तुलनात्मक जिले

- **बिहार बनाम भारत।**

बिहार में गरीबी तेज़ी से घटी है, पर शुरुआती स्तर इतना ऊँचा था कि वह अब भी भारत से बहुत पीछे है। तालिका 1 में दोनों की तुलना है।

तालिका 1: बहुआयामी गरीबी, भारत और बिहार

सूचक	भारत 2015-16	भारत 2019-21	बिहार 2015-16	बिहार 2019-21
MPI मान	0.117	0.066	0.265	0.160
गरीबों का अनुपात H (%)	24.85	14.96	51.89	33.76
गरीबी की तीव्रता A (%)	47.14	44.39	51.01	47.40

स्रोत: नीति आयोग (2023), राज्य सारांश तालिका (भारत और बिहार, दोनों के H, A और MPI)।

बिहार का H 2019–21 में भारत से 18.8 प्रतिशत अंक ऊपर (33.76 − 14.96) और लगभग 2.3 गुना है। भारत में ग्रामीण H (19.28%) शहरी H (5.27%) का लगभग 3.7 गुना है (यूएनडीपी इंडिया, 2023), और NFHS–5 के नमूने में बिहार के लगभग 84% परिवार ग्रामीण थे (पारी, 2021)। इसलिए बिहार के ग्रामीण परिवारों पर गरीबी का बोझ राष्ट्रीय ग्रामीण औसत से भी भारी रहने की आशंका है। इसे बिहार के ग्रामीण–शहरी MPI से जाँचना बाकी है।

- **जिलों के बीच असमानता।**

बिहार के भीतर भी तस्वीर एक–सी नहीं है। तालिका 2 में गया, उसके चार तुलनात्मक जिले (तालिका 3 वाले ही), कम गरीबी वाले छोर के उदाहरण के रूप में पटना और बिहार का औसत एक साथ रखे गए हैं।

तालिका 2: बहुआयामी गरीबी, बिहार के चुने हुए जिले (H और A प्रतिशत में)

क्षेत्र	H 2015-16	H 2019-21	H में गिरावट (अंक)	A 2019-21	MPI 2019-21
बिहार	51.89	33.76	18.13	47.40	0.160
पटना	29.20	23.09	6.12	46.53	0.107
औरंगाबाद	43.94	26.80	17.14	45.72	0.123
अरवल	52.18	31.72	20.47	46.91	0.149
गया	54.67	35.43	19.24	47.61	0.169
बाँका	57.83	38.22	19.61	46.42	0.177
अररिया	64.65	52.07	12.58	51.04	0.266

स्रोतः नीति आयोग (2023), बिहार अध्याय (पृ. 74–81)। H = बहुआयामी गरीबों का अनुपात, A = गरीबी की तीव्रता। गिरावट रिपोर्ट में छपे आँकड़े के अनुसार है; दशमलव के पूर्णांकन से कुछ जिलों में अंतिम अंक का 0.01 का अंतर संभव है।

तालिका से चार बातें निकलती हैं। पहली, गया में 2019–21 में 35.43% लोग बहुआयामी रूप से गरीब थे, जो राज्य औसत (33.76%) से 1.67 प्रतिशत अंक ऊपर है। बिहार के 38 जिलों में H के हिसाब से गया का स्थान 15वाँ सबसे ऊँचा है। NFHS नमूना सर्वेक्षण है, इसलिए इतने छोटे अंतर को राज्य औसत के %आसपास" पढ़ना ठीक है, %काफ़ी ऊपर" नहीं। दूसरी, पड़ोस के जिलों से तुलना में अंतर बड़ा है: औरंगाबाद (26.80%) और पटना (23.09%) गया से क्रमशः 8.63 और 12.34 अंक नीचे हैं, जबकि बाँका (38.22%) गया से 2.79 अंक ऊपर और अररिया (52.07%) 16.64 अंक ऊपर है। तीसरी, 2015–16 से 2019–21 के बीच गया का H 54.67% से 35.43% हुआ, यानी 19.24 अंक की गिरावट, जो राज्य (18.13) से थोड़ी अधिक है; अरवल (20.47) और बाँका (19.61) में गिरावट कुछ अधिक और औरंगाबाद (17.14) में कम रही। चौथी, तीव्रता । (गरीब औसतन भारित अभावों के कितने हिस्से से जूझ रहे हैं) गया में 49.67% से घटकर 47.61% हुई, जो राज्य (47.40%) के लगभग बराबर है, और MPI 0.272 से 0.169 हुआ (राज्य 0.160)। यानी गया में गरीबों का अनुपात राज्य से थोड़ा अधिक है, पर गरीब औसतन उतने ही गहरे अभावों में हैं जितने राज्य में। सबसे ज़्यादा गरीबी वाले अररिया में H और ।, दोनों ऊँचे हैं (52.07% और 51.04%)। पटना में गिरावट केवल 6.12 अंक रही, क्योंकि वहाँ शुरुआती स्तर पहले ही नीचा था। रिपोर्ट में जिले के संकेतक–वार योगदान प्रकाशित नहीं हैं, इसलिए गया की गरीबी किन अभावों से बनती है, यह अगले उप–खंड में NFHS–5 के सीधे संकेतकों से देखा गया है।

- **संकेतकों की तुलना।**

MPI के पीछे के अभावों को समझने के लिए NFHS–5 के कुछ संबंधित संकेतक तालिका 3 में रखे गए हैं।

तालिका 3: चुने हुए NFHS–5 संकेतक (%)

संकेतक	बिहार	अररिया	औरंगाबाद	अरवल	बाँका	गया
6 वर्ष से ऊपर की महिलाएँ जो कभी स्कूल गई	61.1	53.0	65.0	62.6	59.3	59.6
साक्षर महिलाएँ (15-49 वर्ष)	57.8	43.7	67.6	62.5	55.7	59.4
बिजली वाले घरों में रहने वाली आबादी	96.3	96.2	97.7	97.4	96.2	97.9

उन्नत स्वच्छता सुविधा वाले घरों में रहने वाली आबादी	49.4	32.2	47.1	43.4	38.2	44.4
स्वच्छ रसोई ईंधन वाले परिवार	37.8	15.2	38.9	29.3	32.3	34.7
स्वास्थ्य बीमा से कम से कम एक सदस्य कवर	14.6	19.5	15.4	15.6	13.6	9.7
5 वर्ष से कम के ठिगने बच्चे	42.9	49.9	41.2	45.6	46.7	47.4
कम BMI वाली महिलाएँ	25.6	30.4	25.8	31.9	23.8	26.8
एनीमिया पीड़ित महिलाएँ (15-49 वर्ष)	63.5	67.9	60.5	66.9	65.9	64.3

स्रोतः आईआईपीएस (2020), NFHS–5 राज्य एवं जिला फैक्ट शीट, बिहार। गया के जिला–आँकड़े इन्हीं फैक्ट शीट के CSV संस्करण से लिए गए हैं (वर्धन, GitHub)।

इन आँकड़ों से चार निष्कर्ष स्पष्ट हैं। पहला, बिजली अब लगभग हर जगह पहुँच चुकी है (96–98%), इसलिए यह संकेतक अब जिलों के बीच फ़र्क नहीं करता। दूसरा, स्वच्छ रसोई ईंधन पर बिहार में केवल 37.8% परिवार हैं, जबकि भारत में 58.6% (पारी, 2021); जिलों में यह अररिया में 15.2% और औरंगाबाद में 38.9% है, यानी ढाई गुना से ज़्यादा अंतर। तीसरा, महिला साक्षरता में बिहार (57.8%) राष्ट्रीय स्तर (लगभग 72%) से करीब 14 प्रतिशत अंक पीछे है, और अररिया (43.7%) व औरंगाबाद (67.6%) के बीच लगभग 24 प्रतिशत अंक का फासला है। चौथा, पोषण में बिहार के 42.9% बच्चे ठिगने और 63.5% महिलाएँ एनीमिया–पीड़ित हैं (आईआईपीएस, 2020), जबकि भारत में लगभग 36% बच्चे ठिगने हैं (पारी, 2021)। बीमा का आँकड़ा जिलों में 13.6% से 19.5% के बीच है और अंतर छोटा है, इसलिए उससे कोई मज़बूत निष्कर्ष नहीं निकालना चाहिए।

गया की स्थिति। तालिका 3 में गया कई संकेतकों पर बिहार औसत के आसपास, पर थोड़ा पीछे है। उन्नत स्वच्छता में गया 44.4% पर राज्य (49.4%) से 5.0 और औरंगाबाद (47.1%) से 2.7 प्रतिशत अंक पीछे है। स्वच्छ रसोई ईंधन में गया 34.7% है (राज्य 37.8%), और स्वास्थ्य बीमा में 9.7% (राज्य 14.6%)। पोषण में अंतर सबसे बड़ा हैः गया के 47.4% बच्चे ठिगने हैं (उम्र के हिसाब से कम कद, जो लंबे समय के कुपोषण का संकेत है), जो राज्य (42.9%) से 4.5 और औरंगाबाद (41.2%) से 6.2 प्रतिशत अंक अधिक है। इसके उलट, महिला साक्षरता (59.4%, राज्य 57.8%), बिजली (97.9%) और एनीमिया–पीड़ित महिलाएँ (64.3%, राज्य 63.5%) राज्य के लगभग बराबर हैं। चूँकि हर जिले में केवल लगभग हज़ार परिवार सर्वेक्षित हैं, एक–दो अंक के अंतर को वास्तविक अंतर न मानें; स्वच्छता, बीमा और ठिगनेपन के अंतर अपेक्षाकृत बड़े हैं, पर इन्हें भी संकेत भर समझना चाहिए (आईआईपीएस, 2020)।

NFHS–4 से NFHS–5 तक गया का बदलाव। फैक्ट शीट में दोनों दौर के आँकड़े साथ दिए जाते हैं। गया में बिजली वाले घरों की आबादी 73.4% से 97.9%, उन्नत स्वच्छता 28.4% से 44.4%, स्वच्छ रसोई ईंधन 15.6% से 34.7%, स्वास्थ्य बीमा 2.8% से 9.7%, ठिगने बच्चे 52.9% से 47.4% और कम ठडप वाली महिलाएँ 36.1% से 26.8% हुईं, यानी लगभग सभी संकेतकों में सुधार हुआ। पर एनीमिया–पीड़ित महिलाएँ 61.8% से बढ़कर 64.3% हो गईं। राज्य से तुलना करें तो स्वच्छता में बिहार 26.5% से 49.4% (22.9 अंक) पहुँचा, जबकि गया 16.0 अंक ही बढ़ा; गया 2015–16 में राज्य से कुछ आगे (28.4% बनाम 26.5%) था, पर 2019–21 में पीछे रह गया। स्वच्छ ईंधन में बिहार को 20.0 अंक का लाभ हुआ, गया को 19.1 अंक का। ठिगनेपन में गिरावट लगभग बराबर रही (बिहार 5.4, गया 5.5 अंक), इसलिए गया का पुराना अंतर बना रहा (आईआईपीएस, 2020)।

- **सामाजिक असमानता।**

आय आधारित जाति सर्वेक्षण दिखाता है कि अनुसूचित जाति के 42.93% और मुसहर के लगभग 54% परिवार गरीब हैं, जबकि सामान्य वर्ग में 25.09% (द वीक, 2023; जनता वीकली, 2023)। यानी सबसे कमज़ोर

समुदायों में गरीबी सामान्य वर्ग की लगभग दोगुनी है। गया में अनुसूचित जाति की हिस्सेदारी 30.38% है और यह बिहार में सबसे अधिक है (एनएचएसआरसी, 2021)। इन दोनों तथ्यों को जोड़ने पर यह अनुमान बनता है कि गया में गरीबी का बड़ा हिस्सा सामाजिक रूप से वंचित समूहों में केंद्रित होगा। यह अनुमान है, सिद्ध निष्कर्ष नहीं: इसे जाँचने के लिए गया का जाति–वार MPI या जाति–वार आय–गरीबी का जिला आँकड़ा चाहिए, जो इस पत्र में विश्लेषित नहीं है। जनगणना 2011 में गया की साक्षरता (63.67%) पड़ोसी औरंगाबाद (70.32%) से कम और नवादा (59.76%) से अधिक थी (जनगणना 2011 पोर्टल)।

नीतिगत चुनौतियाँ

बिहार के NFHS–4 और NFHS–5 राज्य–आँकड़ों की तुलना बताती है कि सुधार हुआ है, पर असमान रूप से। नीचे की पाँच चुनौतियाँ इन्हीं आँकड़ों से निकलती हैं और गया सहित पूरे राज्य पर लागू होती हैं। योजना–वार क्रियान्वयन–आँकड़े (मनरेगा, सार्वजनिक वितरण प्रणाली, जीविका, प्रधानमंत्री आवास योजना) इस पत्र में विश्लेषित नहीं हैं; इसलिए चुनौतियाँ संकेतकों के स्तर पर हैं, किसी योजना की सफलता या विफलता का दावा नहीं।

- ढाँचे में तेज़ प्रगति, क्षमता में धीमी। बिहार में बिजली वाले घरों में रहने वाली आबादी 60.0% से बढ़कर 96.3%, उन्नत स्वच्छता 26.5% से 49.4% और स्वच्छ रसोई ईंधन 17.8% से 37.8% हुआ। इसके मुकाबले 10 या अधिक वर्ष पढ़ी महिलाएँ 22.8% से 28.8% और ठिगने बच्चे 48.3% से 42.9% पर ही पहुँचे (आईआईपीएस, 2020)। जो अभाव किसी सुविधा के पहुँचाने से मिटते हैं, वे जल्दी घटे; जो अभाव पोषण, शिक्षा और सेवाओं की निरंतरता से घटते हैं, वे धीरे।
- सुविधा मिलना और उसका उपयोग, अलग बातें। बिहार में महिलाओं के अपने बैंक खाते 26.4% से बढ़कर 76.7% हो गए, पर पिछले 12 महीनों में नकद भुगतान वाला काम करने वाली महिलाएँ केवल 12.6% हैं (आईआईपीएस, 2020)। इसी तरह NFHS की %उन्नत स्वच्छता" में साझा शौचालय नहीं गिने जाते, और फैक्ट शीट स्वयं कहती है कि यह संकेतक शौचालय की पूर्ण उपलब्धता नहीं दर्शाता (आईआईपीएस, 2020)। खाता, कनेक्शन या शौचालय बन जाना नीति का पहला चरण है; उसका नियमित उपयोग और आमदनी में बदलना दूसरा, जो ज़्यादा कठिन है।
- माँ और बच्चे के पोषण व सेवाओं की कमज़ोर कड़ी। बिहार में अंतिम प्रसव से पहले कम से कम 4 प्रसवपूर्व जाँच कराने वाली माताएँ 25.2% और 180 दिन या अधिक आयरन–फोलिक एसिड लेने वाली माताएँ 9.3% थीं। 6–23 माह के बच्चों में पर्याप्त आहार पाने वाले केवल 10.9% थे (आईआईपीएस, 2020)। MPI में पोषण और मातृ स्वास्थ्य दोनों संकेतक हैं, इसलिए ये कमियाँ सीधे गरीबी के आँकड़ों में दिखती हैं। साथ ही सरकारी अस्पताल में प्रसव पर औसत जेब–खर्च ₹1,784 से बढ़कर ₹2,848 हो गया (आईआईपीएस, 2020), जो सेवा तो है पर पूरी तरह मुफ़्त नहीं।
- सामाजिक लक्ष्यीकरण। जाति सर्वेक्षण में अनुसूचित जाति के 42.93% और मुसहर के लगभग 54% परिवार गरीब हैं (द वीक, 2023; जनता वीकली, 2023), और गया में अनुसूचित जाति की हिस्सेदारी राज्य में सर्वाधिक है (एनएचएसआरसी, 2021)। जब गरीबी कुछ समुदायों में सघन हो, तब जिले के औसत सुधार से इन समुदायों तक लाभ पहुँचने की गारंटी नहीं मिलती। योजनाओं के लाभार्थी–आँकड़ों को जाति और लिंग के आधार पर अलग करके देखना ज़रूरी है।
- आँकड़ों और निगरानी की सीमा। जिला–स्तर का MPI NFHS–5 पर टिका है, जिसमें हर जिले में लगभग एक हज़ार परिवारों का सर्वेक्षण हुआ (आईआईपीएस, 2020)। यह सर्वेक्षण कुछ वर्षों के अंतर पर आता है, इसलिए नीति की गति सालाना परखना कठिन है। एक साथ कई अभावों से घिरे परिवारों

के लिए अलग–अलग विभाग अलग–अलग योजनाएँ चलाते हैं, पर डच् यही बताता है कि अभाव एक साथ आते हैं, इसलिए जिला–स्तर पर योजनाओं का समन्वय और साझा निगरानी चाहिए।

अध्ययन की सीमाएँ

- गया के आँकड़े। गया का बहुआयामी गरीबी का आँकड़ा (H, तीव्रता और MPI) NFHS–4 और NFHS–5 के नमूनों पर आधारित अनुमान है, जिसमें हर जिले में लगभग एक हज़ार परिवार सर्वेक्षित हैं; इसलिए जिलों के बीच छोटे अंतर (जैसे गया और राज्य औसत के बीच 1.67 अंक) को निर्णायक नहीं माना गया है। नीति आयोग की रिपोर्ट में जिलों के संकेतक–वार योगदान प्रकाशित नहीं हैं, इसलिए गया की गरीबी के कारणों के लिए NFHS–5 के सीधे संकेतक प्रयुक्त हुए हैं।
- द्वितीयक आँकड़े। सभी निष्कर्ष प्रकाशित आँकड़ों पर आधारित हैं। जाति सर्वेक्षण के आँकड़े यहाँ मीडिया–रिपोर्टों से लिए गए हैं; अंतिम प्रकाशन से पहले इन्हें बिहार सरकार की मूल रिपोर्ट से मिलाना चाहिए।
- समय। MPI और NFHS–5 के आँकड़े 2019–21 के हैं। उसके बाद की योजनाओं का असर इनमें नहीं दिखता।
- तुलना का दायरा। तुलना केवल चार जिलों से हुई है और जिला–अनुमानों में नमूने की त्रुटि है, इसलिए छोटे अंतरों पर ज़ोर नहीं दिया गया।
- कार्य–कारण। पत्र संबंध और स्तर दिखाता है, यह सिद्ध नहीं करता कि किसी एक योजना ने गरीबी घटाई या नहीं घटाई।

निष्कर्ष एवं नीतिगत सुझाव

बिहार में बहुआयामी गरीबी 2015–16 से 2019–21 के बीच 51.89% से 33.76% पर आई, जो किसी भी राज्य की सबसे बड़ी गिरावट है, फिर भी राज्य राष्ट्रीय औसत (14.96%) के दोगुने से अधिक ऊपर है। राज्य के भीतर जिलों में गरीबी का स्तर और उसके घटने की रफ़्तार, दोनों में बड़ा अंतर है। अभाव सबसे अधिक स्वच्छ रसोई ईंधन, स्वच्छता, महिला शिक्षा और बच्चों–महिलाओं के पोषण जैसे क्षेत्रों में बचे हैं, जबकि बिजली जैसी सुविधाएँ लगभग सार्वभौमिक हो चुकी हैं। गरीबी सामाजिक समूहों में भी असमान है, और गया में अनुसूचित जाति की सर्वाधिक हिस्सेदारी को देखते हुए जिले की नीति में सामाजिक लक्ष्यीकरण केंद्रीय होना चाहिए। गया में 2019–21 में 35.43% आबादी बहुआयामी रूप से गरीब थी (राज्य 33.76%), यानी राज्य के औसत के आसपास पर राष्ट्रीय औसत (14.96%) से बहुत ऊपर, और 2015–16 (54.67%) से 19.24 अंक की गिरावट आई। MPI 0.169 है और तीव्रता राज्य के लगभग बराबर है। NFHS संकेतकों में गया का ठिगनापन (47.4%, राज्य से 4.5 अंक अधिक) और स्वास्थ्य बीमा (9.7% बनाम 14.6%) में पिछड़ना अपेक्षाकृत बड़ा अंतर है; स्वच्छता और स्वच्छ रसोई ईंधन के छोटे अंतरों को केवल संकेत मानना चाहिए। स्वच्छता में गया 2015–16 में राज्य से आगे था, पर 2019–21 में पीछे रह गया।

सुझाव

- जिला डच् कार्य–योजना। गया के लिए उन संकेतकों की सूची बनाई जाए जिन पर जिला राज्य औसत से पीछे है, और उन्हीं पर लक्ष्य तय हों। राष्ट्रीय डच् का जिला–स्तर विभाजन इसी उद्देश्य से बना है (यूएनडीपी इंडिया, 2023)।
- पोषण और मातृ स्वास्थ्य पर ज़ोर। प्रसवपूर्व जाँच, आयरन–फोलिक एसिड और शिशु आहार की पहुँच बढ़ाने के लिए आँगनवाड़ी और स्वास्थ्य केंद्रों के काम की साझा निगरानी हो।

- उपयोग की निगरानी। खाता, कनेक्शन और शौचालय गिनने के साथ यह भी दर्ज हो कि वे नियमित उपयोग में हैं या नहीं, खासकर रसोई गैस के पुनर्भरण और साझा शौचालय के मामलों में।
- जाति और लिंग–वार आँकड़े। योजनाओं के लाभार्थियों का विवरण अनुसूचित जाति, मुसहर जैसे अति–वंचित समुदायों और महिलाओं के अनुसार प्रकाशित किया जाए।
- महिला शिक्षा और काम। महिला साक्षरता और नकद आय वाले काम में भागीदारी, दोनों को एक साथ लक्ष्य बनाया जाए, क्योंकि बैंक खाते बढ़ने के बावजूद आय वाले काम में महिलाएँ बहुत कम हैं।

संदर्भ गन्थ सूची

1. अल्काइर, एस. एवं फ़ोस्टर, जे. (2011). गणना और बहुआयामी गरीबी मापन (Counting and multidimensional poverty measurement). जर्नल ऑफ पब्लिक इकोनॉमिक्स, 95(7–8), 476–487. doi%10-1016@j-jpubeco-2010-11-006
2. आईआईपीएस (2020). राष्ट्रीय परिवार स्वास्थ्य सर्वेक्षण (एनएफएचएस–5), राज्य एवं जिला फैक्ट शीट, बिहार. अंतर्राष्ट्रीय जनसंख्या विज्ञान संस्थान, मुंबई। तबीपपचे.वतह
3. एनएचएसआरसी (2021). स्वास्थ्य डोज़ियर 2021ः प्रमुख स्वास्थ्य संकेतकों पर विचार, बिहार. राष्ट्रीय स्वास्थ्य प्रणाली संसाधन केंद्र। nhsrcindia-org
4. जनगणना 2011 पोर्टल. बिहार के जिलों की सूची (जनगणना 2011 के आँकड़े). census2011-co-in
5. जनता वीकली (2023, 11 नवंबर). बिहार जाति सर्वेक्षणः अनुसूचित जाति/जनजाति में सबसे अधिक गरीब परिवार, फिर पिछड़ा/अत्यंत पिछड़ा वर्ग. janataweekly-org
6. द वीक (2023, 7 नवंबर). बिहार में एक–तिहाई से अधिक परिवार ₹6,000 प्रति माह या उससे कम पर गुज़ारा करते हैंः सर्वेक्षण. theweek-in
7. नीति आयोग (2021). राष्ट्रीय बहुआयामी गरीबी सूचकांकः आधार रिपोर्ट 2021. आँकड़े समाचार–सार से लिए गएः द न्यूज़ मिनट, केरल, तमिलनाडु भारत के सबसे कम गरीब राज्यों में; सिविल्सडेली, नीति आयोग का बहुआयामी गरीबी सूचकांक
8. नीति आयोग (2023). राष्ट्रीय बहुआयामी गरीबी सूचकांकः प्रगति समीक्षा 2023. नई दिल्लीः नीति आयोग, भारत सरकार (राज्य और जिला–स्तरीय H, A और MPI के आँकड़े; बिहार अध्याय पृ. 74–81)। niti-gov-in
9. पारी. राष्ट्रीय परिवार स्वास्थ्य सर्वेक्षण (एनएफएचएस–5) 2019–21ः बिहार. ruralindiaonline-org
10. पारी. राष्ट्रीय परिवार स्वास्थ्य सर्वेक्षण (एनएफएचएस–5), 2019–21ः भारत. ruralindiaonline-org
11. मेन मीडिया (2023). बिहार सबसे गरीब राज्य, अररिया सबसे गरीब जिलाः नीति आयोग की रिपोर्ट. mainmedia-in
12. यूएनडीपी इंडिया (2023). राष्ट्रीय बहुआयामी गरीबी सूचकांकः प्रगति समीक्षा 2023. नीति आयोग, यूएनडीपी और ओपीएचआई की रिपोर्ट का सार–पृष्ठ। undp-org
13. वर्धन, पी. एनएफएचएस–5ः राज्यों और जिलों की CSV फैक्ट शीट, बिहार. आईआईपीएस फैक्ट शीट का तृतीय–पक्ष CSV संस्करण। github.com/pratapvardhan/NFHS–5
14. सेन, ए. (1976). गरीबीः मापन का क्रमसूचक दृष्टिकोण (Povertyः An ordinal approach to measurement). इकोनोमेट्रिका, 44(2), 219–231. jstor-org

❑❑❑